Newspaper Clips

September 25, 2012

Amar Ujala ND
25-Sep-12 P-6

आईआईटी के लिए ही एडवांस टेस्ट

कानपुर (ब्यूरो)। एनआईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ट्रिपल आईटी सहित अन्य इंजीनियरिंग संस्थानों की सीटें ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम (जेईई) मेंस 2013 से ही भरी जाएंगी। इसमें सफल सभी स्टूडेंट के लिए जेईई एडवांस में शामिल होना अनिवार्य नहीं रहेगा। जेईई एडवांस का आयोजन सिर्फ आईआईटी के बीटेक पाठ्यक्रम में एडमिशन के लिए कराया जाएगा। इसका अंतिम ब्योरा जारी कर दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कहा है कि एंट्रेंस एग्जाम के नए पैटर्न से स्टूडेंट का बोझ कम हो जाएगा।

एनआईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ट्रिपल आईटी में एडमिशन के लिए जेईई मेंस 2013 के ऑनलाइन फार्म 1 नवंबर से भरे जाएंगे। यह प्रक्रिया 15 दिसंबर तक चलेगी। इसका ब्योरा वेबसाइट www.jeemains.edu.in पर उपलब्ध है। आईआईटी कानपुर के कार्यवाहक रजिस्ट्रार डॉ. आरके सचान ने बताया कि जेईई मेंस में जो स्टूडेंट सफल होंगे, उनकी मेरिट बनेगी। इसका फार्मूला तय हो गया है। जेईई मेंस से 60 फीसदी अंक और बोर्ड परीक्षा से 40 फीसदी अंक लेकर मेरिट सूची बनाई जाएगी।

REVISED FORMAT

- JEE (Main) application forms will be available from November 1 on www.jeemain-edu.in
- April 7: JEE (Main) offline exam
- April 8 to April 30 (exact dates to be announced): JEE (Main) online exam
- JEE (Advanced) will be held in the pen-paper mode on June 2, for further queries candidates can contact jeeadv@admin.iitd.ac.in or http://jee.iitd.ac.in
- The preliminary list of facilitation centres is available in pdf format at http://www.jeemain-edu.in

Virat Vaibhav ND 25/09/2012

P-8

ऑनलाइन भरे जाएंगे जेईई मेंस और एडवांस के फार्म

कानपुर।आईआईटी, ट्रिपल आईटी, एनआईटी में दाखिले के लिए प्रस्तावित ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम (जेईई) मेंस और जेईई एडवांस के ऑफ लाइन फॉर्म भरने की सुविधा खत्म कर दी गई है। इस बार से ऑनलाइन फॉर्म ही भरे जा सकेंगे। जेईई एडवांस के फार्म अक्तूबर के पहले सप्ताह से भरे जाएंगे। यह प्रक्रिया 15 दिसंबर तक चलेगी।

जेईई मेंस, जेईई एडवांस के आयोजन को लेकर रविवार को ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड (जैब) की महत्वपूर्ण बैठक नई दिल्ली में हुई। इसमें सभी आईआईटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर (बीओजी) चेयरमैन, निदेशक और जेईई चेयरमैन शामिल हुए।विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि बैठक में चर्चा के बाद तय हुआ कि इस बार से सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म ही भरवाए जाएंगे। जो छात्र जेईई मेंस के फार्म भरेंगे, उन्हें जेईई एडवांस का विकल्प भी लॉक करना होगा। जेईई मेंस का आयोजन 7 अप्रैल, 2013 को होना है।सीबीएसई की देखरेख में होने वाले इस एंट्रेंस एग्जाम की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। फॉर्म भरने की पहली, आखिरी तारीखें भी तय हो चुकी हैं।

जल्द ही पूरा ब्योरा वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। जेईई मेंस के रिजल्ट मई के पहले सप्ताह तक आ जाएंगे।

इसमें सफल 1.50 लाख स्टूडेंट जेईई एडवांस में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन कराएंगे। रजिस्ट्रेशन फीस में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है।ऑनलाइन फॉर्म भरने वाले सामान्य, ओबीसी संवर्ग के स्टूडेंट को 1800 रुपये, एससी, एसटी के स्टूडेंट को 1000 रुपये फीस जमा करनी होगी। सभी संवर्ग की लड़कियां फ्री में रजिस्ट्रेशन करा सकेंगी। जेईई एडवांस का आयोजन 2 जून 2013 को होना है। इसकी जिम्मेदारी आईआईटी दिल्ली को सौंपी जा चुकी है। सीबीएसई के चेयरमैन डॉ. विनीत जोशी ने बताया कि इंजीनियरिंग के सिंगल एंट्रेंस एग्जाम के फार्म अक्तूबर के पहले सप्ताह से भरे जाएंगे।■

Pioneer ND 25/09/2012 P7

Super 30 free online classes soon

DHEERAJ KUMAR ■ PATNA

Super 30, an innovative educational programme which has caught the imagination of the people across the globe by preparing 30 underprivileged students every year to face the IIT Joint Entrance Examination (JEE) will go online soon.

Founder of Super 30, Anand Kumar told *The Pioneer* on Monday that in addition to IIT JEE, the free online classes will be available for students of Standards IX, X, XI and XII too. It will help lakhs of students who always want to take the support of Super 30 for shaping their careers but cannot do so because Super 30 prepares mainly such students who belong to poor sections of the society.

In all, 263 students from economically backward sections of the society have taken admissions to various IITs since 2003 when the Super 30 was set up.

Kumar said that the free online classes will be available from the beginning of the next year. He said students have become tech-savvy over the years and it is expected that several of them will be carrying iPads in the next five years. In such a situation, online classes will be an instant hit. Lecture videos will be uploaded for the benefit of students who can also download assignments and appear in online tests. Super 30 is consulting a web designer to give a final shape to the online classes project.

Students will have to clear preliminary level test to reach the final test of the online classes. Kumar said that tests have been divided into three different levels, adding a student will be provided a password once he passes the first or the second level of the online test so that he can advance to the next level of the test. Students will also be prepared for International Mathematical Olympiad through online classes.

American Professors, Jerry Dywer and Peter Vachusaka are also supporting Anand Kumar in his endeavour to launch online classes for lakhs of students.

Bollywood director Anurag Basu of *Barfi* fame has also planned a film on Super 30 and Anand Kumar, the first choice for the role of Anand Kumar in the film is Ranbir Kapoor while the second choice rests with Abhishek Bachchan. The film is likely to be released in January-February in 2014, Kumar added.

Not only filmmakers but reputed publishing houses like Penguin, Rupa and Prabhat Prakashan have also expressed their willingness to publish books on the success of Super 30. A Korean publication house is already publishing a book on Super 30 and Anand Kumar in Korean language.

Anand Kumar's achievement has also inspired Navodaya Vidyalaya in Bangalore and the Punjab Government, which are preparing students for various competitive examinations on the Super 30 model.

Dainik Tribune, ND 25/09/2012 p-9

चिंताजनक है इंजीनियरिंग शिक्षा के प्रति घटता रुझान

▶ शशांक द्विवेदी

देश में इंजीनियरिंग के मौजूदा सत्र में भी देश के सभी राज्यों में बड़े पैमाने पर सीटें खाली रह गयी हैं। पूरे देश में लगभग साढ़े तीन लाख से ज्यादा सीटें खाली रह गयीं। राजस्थान में तो 50 प्रतिशत से ज्यादा लगभग 35 हजार सीटें खाली रह गयीं। यही हाल उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में भी है। इंजीनियरिंग के पिछले सत्र में पूरे देश में ढाई लाख से ज्यादा सीटें खाली रह गयी थीं। पिछले दिनों देश के चौदह राज्यों से 143 तकनीकी शिक्षण संस्थानों को एआइसीटीई से अपने पाठ्यक्रम बंद करने की इजाजत मांगनी पड़ी इससे सीटें न भर पाने से देश के कई कॉलेजों में जीरो सेशन का खतरा पैदा हो गया है। जहां कुछ साल पहले तक निजी तकनीकी शिक्षण संस्थान खोलने की होड़ थी तो अब इन्हें बंद करने की इजाजत मांगने वालों की लाइन लगी हुई है। अकेले आंध्र प्रदेश से ही 56 संस्थानों ने अपने पाठ्यक्रम बंद करने की इजाजत मांगी है।

असल में देश में तकनीकी शिक्षा के हालात साल-दर-साल खराब होते जा रहे हैं और सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि हमारे देश के नीति नियंताओं को मौजूदा हालत नजर क्यों नहीं आ रही है? जबकि तकनीकी शिक्षा की यह स्थिति सीधे-सीधे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगी। इस बात पर राष्ट्रीय बहस होनी ही चाहिए कि लोगों का रुझान इंजीनियरिंग में कम क्यों हो रहा है और इतनी सीटें खाली कैसे रह गई? अगर कोई कमी है तो उसे कैसे दूर किया जाये?

देश में इंजीनियरिंग के दाखिलों में साल-दर-साल जो गिरावट आ रही है उसके पीछे कुछ मुख्य कारण हैं जिन्हें हमें समझना होगा। मसलन, तकनीकी शिक्षा के इतने विस्तार के बाद भी आज हम उसे व्यावहारिक और रोजगारपरक नहीं बना पाए हैं। कोई भी अभिभावक इंजीनियरिंग में अपने बच्चों को दाखिला सिर्फ इसलिए कराता है कि उसको डिग्री के बाद नौकरी मिले। देश में इस धारणा को समझना होगा कि इंजीनियर बनने के लिए कोई इंजीनियरिंग नहीं पढ़ता बल्कि नौकरी पाने के लिए इंजीनियरिंग पढ़ता है। नौकरी की गारंटी पर ही लोगों का इंजीनियरिंग में रुझान था लेकिन आज स्थिति एकदम बदल गयी है। बेरोजगार इंजीनियरिंग स्नातकों की पूरी फौज खड़ी हो गयी है। लोगों में यह आम धारणा हो गयी कि जब बेरोजगार ही रहना है तो ज्यादा पैसे खर्च कर इंजीनियरिंग क्यों करें, कुछ और करें। अधिकांश इंजीनियरिंग कालेजों में डिग्री के बाद प्लेसमेंट और खपत की गारंटी न होना मोहभंग होने का प्रमुख कारण है।

असंगत पाठ्यक्रम

इंजीनियरिंग स्नातकों में बेरोजगारी बढ़ने की मुख्य वजह इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट्स के बीच दूरी बढ़ना है। इनके बीच मांग और आपूर्ति का फासला बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों आई टी दिग्गज नारायणमूर्ति ने कहा था कि सूचना प्रौद्योगिकी इंडस्ट्री को प्रशिक्षित इंजीनियर नहीं मिलते। कॉलेज इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से इंजीनियर पैदा नहीं कर पा रहे हैं जबकि इंडस्ट्रीज में कुशल मानव संसाधन की कमी है। देश के 13 राज्यों के 198 इंजीनियरिंग कॉलेजों में अंतिम वर्ष के 34 हजार विद्यार्थियों पर हुए एक हालिया सर्वेक्षण के मुताबिक देश के सिर्फ 12 फीसदी इंजीनियर नौकरी करने के काबिल हैं। इस सर्वे ने भारत में उच्च शिक्षा की शर्मनाक तस्वीर पेश की है। यह आंकड़ा चिंता बढ़ाने वाला भी है, क्योंकि स्थिति साल दर साल खराब ही होती जा रही है।

वास्तव में इंडस्ट्री की जरूरत और छात्रों के ज्ञान में कोई तालमेल नहीं है। वजह यह है कि आज भी हमारे शैक्षिक कोर्स 20 साल पुराने हैं। पाठ्यक्रमों में सालोंसाल कोई बदलाव न होना उच्च शिक्षा की एक बड़ी कमी है। खासतौर पर इंजीनियरिंग में, क्योंकि इस क्षेत्र में नयी-नयी तकनीकें विकसित होती रहती हैं। इसलिए इंडस्ट्री के हिसाब से छात्रों को अपडेटेड थ्योरी नहीं मिल पाती। अभी स्थिति यह है कि सारा ध्यान थ्योरी सब्जेक्ट पर है, उन्हें रटकर पास करने में ही छात्र अपनी इतिश्री समझते हैं। घिसे-पिटे कोर्स से जो शिक्षा दी जाती है, उससे तैयार होने वाले ग्रेजुएट हर दिन बदलती तकनीकी दुनिया से तालमेल नहीं बैठा पाते। ऐसे में उन्हें डिग्री के बाद तुरंत नौकरी मिलेगी इसकी उम्मीद बहुत कम होती है। पूरे 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद उन्हें फिर अपना नालेज अपडेट करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कोर्सेस में दाखिला लेना पड़ता है तब जाकर उन्हें कंपनियों में एक प्रशिक्षु के रूप में ही नौकरी मिल पाती है।

उधर आर्थिक मंदी का भी प्रभाव इंजीनियरिंग के दाखिले पर पड़ा है। जो अभिभावक पहले आराम से इंजीनियरिंग की फीस भर देते थे मंदी के कारण अब ऐसा नहीं हो पा रहा है। पिछले 5 सालों में देश के कई हिस्सों में फीस 2 से 3 गुना तक बढ़ गयी। उत्तर प्रदेश में जहां 2001-05 में बीटेक के लिए बीस हजार रुपये सालाना फीस थी, वर्तमान में लगभग एक लाख रुपये सालाना हो गयी है। यानी 7 सालों में फीस में 5 गुना वृद्धि। फीस में लगातार वृद्धि और आर्थिक मंदी ने दाखिले पर गहरा प्रभाव डाला है। लेकिन मंदी के साथ साथ इस स्थिति के जिम्मेदार कालेज संचालक भी हैं जिन्होंने गुणवत्ता की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और इंजीनियरिंग कालेज खोलने को एक कमाऊ उपक्रम का हिस्सा मान लिया। अधिकांश निजी तकनीकी शिक्षा संस्थान बड़े व्यापारिक घरानों, नेताओं और ठेकेदारों के व्यापार का हिस्सा बन गए। जो इसके जरिए सिर्फ रुपया बनाना चाहते हैं। उनकी प्राथमिकता में गुणवत्ता और छात्रों के प्रति जवाबदेही रही नहीं। इससे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में रुझान बहुत नकारात्मक हुआ है।

दुर्भाग्य से देश में जो तकनीकी शिक्षा का स्तर है वह ठीक नहीं है। देश में इतने बड़े पैमाने पर सीटें खाली रहना बहुत बड़ा मामला है अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो देश को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। सरकार का सारा ध्यान आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थानों पर रहता है जबकि देश के विकास में निजी इंजीनियरिंग कालेजों का ज्यादा योगदान है क्योंकि 95 प्रतिशत इंजीनियर यही कालेज पैदा करते हैं। अगर इनकी दशा खराब होगी तो इसका असर पूरे देश पर पड़ेगा।

Dainik Jagaran ND 25/09/2012 P12

शिक्षा पर राउंट टेबल कान्फ्रेंस

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आल इंडिया काउंसिल आफ टेक्निकल एजुकेशन और कन्फेडरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआइआइ) के साथ मिलकर दो दिवसीय राउंडटेबल कान्फ्रेंस का आयोजन कर रहा है। इस कान्फ्रेंस की अध्यक्षता मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल करेंगे। सीआइआइ के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी स्वागत भाषण देंगे। कान्फ्रेंस में शिक्षा से जुड़े देश भर के दिग्गज हिस्सा लेंगे।

National Duniya ND 25/09/2012 P-9

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल सोमवार को नई दिल्ली में थीम आधारित इनोवेशन इंस्टीट्यूट की स्थापना के बारे में सरकार-उद्योग साझेदारी के बारे में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे। फोटो : एच.एस. चंदेल

शिक्षा विधेयकों के पारित नहीं होने पर सिब्बल ने विपक्ष पर निशाना साधा

नई दिल्ली (भाषा)। मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने संसद में उच्च शिक्षा सुधार से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयकों के पारित नहीं होने पर विपक्ष पर निशाना साधा है। सिब्बल ने कहा कि इसके कारण निर्णय लेने की प्रक्रिया 'पंगु' हो रही है। सिब्बल ने कहा कि सरकार इंटरनेट पर नियंत्रण के खिलाफ है। लेकिन वह चाहती है कि भविष्य में सामने आने वाले मुद्दों को लेकर भागीदारों में आमसहमति हो।

सिब्बल ने कहा कि विपक्षी दल इन महत्वपूर्ण विधेयकों का मार्ग बाधित करना जारी रखे हुए है। मैं समझता हूं कि इसके कारण भारत के भविष्य और लोगों को नुकसान हो रहा है। सरकार के निर्णय करने में किसी तरह के पंगुता की स्थिति नहीं है। बल्कि संसद को पंगु बनाया जा रहा है जहां कानून के विधेयकों को पारित करके निर्णय लेने की अनुमति नहीं दी जा रही है। सरकार

■ इंटरनेट पर नियंत्रण के खिलाफ सरकार : सिब्बल

उद्योग के बीच गठजोड़ के आधार पर केंद्रित नवोन्मेष केंद्र स्थापित करने पर आयोजित गोलमेज बैठक को संबोधित करते हुए मंत्री ने अफसोस जताया कि विपक्षी दल इन विधेयकों पर चर्चा कराने की अनुमति नहीं दे रही है जबकि संसद की स्थायी समिति से इन्हें मंजूरी मिल गई है जिसमें विभिन्न राजनीतिक दल शामिल होते हैं।

एक सम्मेलन में सिब्बल ने कहा कि संभवतः लोकतंत्र का सबसे अच्छे ढंग से प्रतिनिधित्व करने वाले किसी माध्यम के जरिए सूचनाओं के प्रसार में कोई औपचारिक सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, हम तो सहमति चाहते हैं न कि कोई फैसला। सहमति जिसे बाद में औपचारिक रूप देकर भविष्य में उठने वाले मुद्दों से निपटा जा सके। मंत्री ने कहा कि इंटरनेट के कुछ पहलुओं को अभिव्यक्ति की आजादी से पूरी तरह संरक्षण मिला हुआ है लेकिन कुछ पहलू शायद मुक्त अभिव्यक्ति से संरक्षित नहीं हों।

उन्होंने कहा कि समय के साथ व्यवस्था संचालन की प्रकृति, आजादी की परिभाषा के हिसाब से ही बदल रही है। उन्होंने सम्मेलन के शीर्षक पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि मुझे यह शब्द गवर्नेंस पसंद नहीं है। आप यहां इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस सम्मेलन की तैयारी के सिलसिले में इसका आयोजन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम गलत कदम से शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे भारत अपने लोकतंत्र को और मजबूत करेगा, देश इंटरनेट को अंगीकार करेगा।

Maha medha Nd 25-09-2012 P-14

देश में बनाएं जाएंगे 50 शोध पार्क : सिब्बल

नई दिल्ली (ए)। मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उद्योग जगत को अकादमिक जगत और सरकार के साथ मिलकर काम करने का आह्वान करते हुए सोमवार को कहा कि पंचवर्षीय योजना में देश के पांच हजार करोड़ रुपये की लागत से 50 शोध पार्क बनाए जाएंगे और संबद्ध मंत्रालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बजट का दो प्रतिशत शोधकार्य पर खर्च किया जाएगा।

श्री सिब्बल ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईटीसी) और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए यह बात कही। गौरतलब है कि गत दिनों विश्व के 200 शीर्ष संस्थानों में एक भी भारतीय शैक्षणिक संस्थान का नाम न होने पर उच्च शिक्षा में गुणवत्ता को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर चिंता जाहिर की गई। उन्होंने कहा कि यह चिंताजनक बात है कि उद्योग जगत के लोगों का संबंध अकादमिक जगत से नहीं है और उनके बीच कोई संवाद या समन्वय नहीं है। उन्होंने इस बात पर भी चिन्ता जताई कि आज देश में 12 हजार तकनीकी संस्थान निजी क्षेत्र में चल रहे हैं पर उद्योग जगत की उसमें कोई भागीदारी नहीं है। ये संस्थान वे लोग चला रहे हैं, जिनका अकादमिक जगत से कोई वास्ता नहीं है। अगर उद्योग जगत के लोग आगे आकर तकनीकी संस्थान खोले तो देश में उच्च शिक्षा का स्तर बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत, अकादमिक जगत तथा विभिन्न मंत्रालयों को आपस में मिलकर एक 'शैक्षिक त्रिकोण' बनाने की जरूरत है और उसे देश के विकास के लिए कोई मैप तैयार करना चाहिए। श्री सिब्बल ने कहा कि 12वीं पंचवर्षीय में 50 शोध पार्क बनाए जाएंगे और हर पार्क पर एक अरब रुपये खर्च आएगा। इस तरह 5000 करोड़ रुपये के खर्च में से ये पार्क बनाए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि केन्द्र सरकार के मंत्रालय तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपने बजट का दो प्रतिशत शोध कार्य पर खर्च करेंगे। योजना आयोग ने 12वीं पंचवर्षीय योजना में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

'शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि के लिए सरकार, उद्योग व अकादमिक जगत मिलकर करें काम'

कार्यशाला में जब उद्योग जगत से जुड़े लोगों ने शोध एवं तकनीकी संस्थान खोलने के लिए सरकार से जमीन की मांग की तो श्री सिब्बल ने सुझाया कि उद्योग जगत को चाहिए कि वे ये संस्थान विश्वविद्यालयों तथा आईआईटी या भारतीय विज्ञान संस्थान जैसी शैक्षणिक संस्थाओं के साथ मिलकर खोल सकते हैं। सरकार उन्हें इस दिशा में मदद करेगी। श्री सिब्बल ने कहा कि उच्च शिक्षा में गुणवत्ता तभी सुधरेगी जब संसद में शिक्षा संबंधी लंबित विधेयक पारित हो पर विपक्ष संसद को चलने नहीं देता। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले सत्र में भी संसद नहीं चलने दी, इसलिए शिक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण विधेयक पास ही नहीं हो सके। उच्च शिक्षा सचिव अशोक ठाकुर ने कहा कि यह खुशी की बात है कि भारत, अमेरिका के बाद विश्व का दूसरा देश बन गया जहां उच्च शिक्षा में इतनी संख्या में छात्र पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में उच्च शिक्षा में शोधकार्य का स्तर अच्छा नहीं है। रेलवे में अब तक केवल नौ पीएचडी हुई हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष एसएस मैथा ने कहा कि देश में 22 लाख छात्र तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं पर केवल 25 प्रतिशत छात्र ही रोजगार के योग्य हैं, क्योंकि उनका कौशल विकास ही नहीं हो पाया है तथा 33 प्रतिशत नियोक्ता उनके कार्य से संतुष्ट नहीं हैं।

कार्यशाला को मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री ई. अहमद, सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी तथा उच्च शिक्षा पर सीआईआई की राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष पी.राजेंद्रन ने भी संबोधित किया।

MYTHBUSTED

Foreigners avoid top UK universities

Asian News International
letters@hindustantimes.com

LONDON: A majority of foreign students who come to Britain, attend 'lower level' universities and colleges, a study has revealed.

The report by the think tank, MigrationWatch, has revealed that just 5% of the students who come every year, go to a university rated in the top ten.

Around one in eight goes to one of the top 24 Russell group universities. The study said it was a myth that non-EU students coming to the United Kingdom were the "brightest and the best". According to the Daily Mail, only a small percentage of foreign students go to a top ten university.

"This report lifts the lid on what is really happening in the university sector," Sir Andrew Green, chairman of Migration Watch said.

BHU Prof, NBRI director win CSIR award

VARANASI: Prof HB Singh of the department of mycology and plant pathology, Institute of Agricultural Sciences, BHU, along with Dr CS Nautiyal, director, National Botanical Research Institute (CSIR-NBRI), Lucknow and directorate of Agriculture, UP has been selected as winner of the prestigious 'CSIR Award for S&T Innovation for Rural Development (CAIRD)-2011.' Prime Minister Manmohan Singh would present the award on September 26 at Vigyan Bhavan, New Delhi.